सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹02

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

कानपुर, शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025
वर्षः 02, अंकः 199, पृष्ठः 8+4

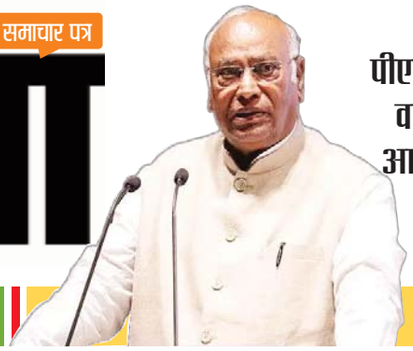

पीएम पर तीखा वार, बीजेपी-आरएसएस पर भी साधा निशाना

» Pg 12

इनसाइड ...पटकथा सीएमओ डॉ. नेमी ने लिखी? » Pg 03

पहली बार चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में होगा

भारत बनाम भारत

ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच खिताबी टक्कर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा करीब है। FIDE महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में अब दो भारतीय ग्रैंडमास्टर्स कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख आमने-सामने होंगी। गुरुवार को सेमीफाइनल के टाईब्रेकर मुकाबले में कोनेरू हम्पी ने चीन की ग्रैंडमास्टर ली टिंगजी को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की, जबकि दिव्या देशमुख ने चीन की ही तान झोंगयी को मात दी। इस जीत के साथ न केवल भारत को पहली बार महिला विश्व कप का खिताब मिलेगा, बल्कि हम्पी और दिव्या दोनों ने अगले साल होने वाले वुमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।

हम्पी ने दिखाया चैंपियन का जज्बा : सेमीफाइनल का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पहले दोनों क्लासिकल गेम्स ड्रॉ रहे, जिसके बाद रैपिड टाईब्रेकर में भी 1-1 की बराबरी हुई। इसके बाद 10-10 मिनट के दो और गेम हुए, जहां पहली बाजी हम्पी हार गईं। जिसके बाद हम्पी को वापसी की जरूरत थी और फिर हम्पी ने अगला गेम जीत लिया।

» हम्पी और दिव्या दोनों ने अगले साल होने वाले वुमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया

तीसरे टाईब्रेकर सेट में हम्पी ने शतरंज के हर विभाग में ली टिंगजी को पीछे छोड़ते हुए पहला गेम जीत लिया। इसके बाद दूसरे गेम में भी तकनीकी श्रेष्ठता दिखाते हुए जीत दर्ज की और फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं 18 वर्षीय दिव्या देशमुख ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में तान झोंगयी को हराया। दिव्या के आत्मविश्वास और रणनीति ने उन्हें उनके करियर के सबसे बड़े फाइनल तक पहुंचाया। फाइनल मुकाबला शनिवार, 26 जुलाई से शुरू होगा। पहला गेम 26 जुलाई को, दूसरा 27 जुलाई को खेला जाएगा। अगर स्कोर बराबरी पर रहता है, तो 28 जुलाई को टाईब्रेकर खेला जाएगा।

क्या है इनाम? : FIDE महिला विश्व कप विजेता को $50,000 (करीब 41.6 लाख रुपए) की पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि उपविजेता को $35,000 (करीब 29.1 लाख रुपए) मिलेंगे।

हो रही थी खुदाई

नाली से निकला 'खजाना'

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के थाना क्वार्सी क्षेत्र के भरेती गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब पानी निकासी के लिए की जा रही खुदाई के दौरान जमीन से 11 छोटे-छोटे सोने के सिक्के निकल आए। खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए। गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए चल रहे खुदाई कार्य के दौरान मजदूरों ने मिट्टी के नीचे दबे सोने के सिक्के खोजे, जिसके बाद मजदूरों ने तुरंत काम रोक दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खुदाई का काम तत्काल बंद करवा दिया गया। जिला प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को सूचित कर दिया है।

बेशर्मी

वीडियो बनता देख हाईवे पर निर्वस्त्र ही दौड़ पड़ा युवक, महिला बाथरुम में छिपी

होटल के कमरे में बिना कपड़ों के मिले शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक विवाहित महिला अपने प्रेमी के साथ ओयो होटल में आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई। परिजनों ने पीछा कर होटल के कमरे में दोनों को नग्न अवस्था में पाया, जिसके बाद प्रेमी बिना कपड़ों के ही भाग निकला।

हापुड़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां ओयो होटल में एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई। यह मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के एक होटल का है, जो अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, महिला कई दिनों से अपने प्रेमी के साथ गुपचुप तरीके से मिल रही थी, लेकिन इस बार उसके परिजनों को शक हो गया। परिजनों ने महिला का पीछा किया और आखिरकार एक ओयो होटल में जा पहुंचे। होटल के एक कमरे का दरवाजा जबरन खोला गया तो वहां जो नजारा था, उसने सभी को हैरान कर दिया। महिला और उसका प्रेमी कमरे में नग्न अवस्था में पाए गए। गुस्साए परिजनों ने तत्काल प्रेमी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब प्रेमी को अहसास हुआ कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है, तो वह घबरा गया और बिना कपड़ों के ही कमरे से भाग निकला। वह हाईवे की ओर दौड़ते हुए काफी दूर तक नग्न अवस्था में भागता रहा। परिजनों ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। इस दृश्य को कई राहगीरों ने भी देखा और कुछ ने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और होटल की भूमिका को भी खंगाला जा रहा है।

नगर निगम मुख्यालय में मेयर इलेवन के विजयी खिलाड़ियों का सम्मान

» पालिका स्टेडियम में हुए मैत्री मैच में मेयर इलेवन ने सीपी इलेवन को 6 विकेट से दी मात

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। द स्पोर्ट्स हब, पालिका स्टेडियम (आर्यनगर) में आयोजित मेयर इलेवन और सीपी इलेवन के बीच हुए टी-20 मैत्री क्रिकेट मुकाबले में मेयर इलेवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीपी इलेवन को 6 विकेट से शिकस्त दी।

इस रोमांचक मुकाबले के विजेता खिलाड़ियों को आज नगर निगम

मुख्यालय में महापौर द्वारा सम्मानित किया गया।सम्मान समारोह में महापौर के साथ पार्षद सौरभ देव, योगेन्द्र शर्मा, नीरज वाजपेई और आकर्ष बाजपेयी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। महापौर ने खिलाड़ियों को स्मृति चिह्न भेंट कर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर महापौर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से खेल भावना को बल मिलता है और टीमवर्क व अनुशासन जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता है।

उन्होंने भविष्य में और भी ऐसे आयोजनों की संभावना जताई।गौरतलब है कि यह मैच दोनों टीमों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और खेल के प्रति उत्साह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

खाद की 30 दुकानों पर ताला, बगैर जांच लाइसेंस निलंबित

डीएम बोले- गलत निलंबन पर अफसरों से जवाब होगा तलब

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शिवराजपुर ब्लॉक के इंधना गांव के रहने वाले विजय सिंह ने खाद की दुकान का लाइसेंस तो लिया, लेकिन आज तक दुकान पर खाद की बिक्री नहीं की। कभी कोई टीम इनकी दुकान पर जांच करने नहीं आई। कृषि उप निदेशक ने लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की तो कृषि अधिकारी ने कार्रवाई कर दी। इसके बाद दुकानदार डीएम-कृषि अधिकारी के पास गुहार लगा रहा है।

शिवराजपुर ब्लॉक के नधिया बुजुर्ग के खाद दुकानदार आशुतोष मिश्रा ने बताया कि 16 जुलाई को कोई भी जांच टीम दुकान पर पहुंची ही नहीं थी। इसके बावजूद अगले दिन कृषि अधिकारी ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। दुकानदार ने जिला कृषि अधिकारी से लाइसेंस बहाल करने की गुहार लगाई है।कानपुर में खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने उर्वरक की 32 दुकानों पर छापे मारे। 30 दुकानें बंद मिलीं, तो अफसरों ने बिना नोटिस दिए इन सभी दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। नियमत- बिना जवाब तलब किए बिना लाइसेंस निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। दो अन्य दुकानों में स्टॉक में हेरफेर मिला, तो उनका लाइसेंस निलंबित किया गया है।शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी और अपर जिला कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में टीम नामित की थी। 16 जुलाई को टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में दुकानों पर छापा मारा था। शाम तक कुल 71 दुकानों का निरीक्षण किया गया। 16 नमूने लिए गए और 32 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे।इनमें 30 दुकानें ऐसी थीं, जिनमें निरीक्षण के दौरान ताला बंद मिला था। सबसे ज्यादा 19 दुकानों का लाइसेंस उप कृषि निदेशक की संस्तुति पर निलंबित किया गया। कृषि अधिकारी ने चार, कृषि रक्षा अधिकारी ने सात दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया।

स्वास्थ्य विभाग

आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा

जेएम फार्मा के खिलाफ साजिश की पटकथा सीएमओ डॉ. नेमी ने लिखी?

» सवालों के घेरे में विभागीय जांच, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की कार्रवाई पर भी उठे सवाल

»सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग में माफिया राज चल रहा है

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और निष्पक्षता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जेएम फार्मा के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई अब विवादों में आ गई है। हाल ही में प्राप्त एक आरटीआई जवाब ने यह संकेत दिए हैं कि पूरी कार्रवाई पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसकी पटकथा खुद सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने तैयार की थी।

इस आरटीआई का जवाब तत्कालीन सीएमओ डॉ. उदयनाथ और एसीएमओ स्टोर डॉ. आरपी मिश्रा के हस्ताक्षर से जारी हुआ, जिसमें साफ तौर पर स्वीकार किया गया है कि जांच रिपोर्ट सीएमओ डॉ. नेमी के दबाव में तैयार की गई थी।

जिन्होंने जांच की, वही खरीद समिति में भी थे!

सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉ. आरपी मिश्रा, जिन्होंने आरटीआई में सच्चाई उजागर की है, वही जांच समिति और खरीद समिति दोनों में शामिल थे। यानी जिन पर निष्पक्षता की जिम्मेदारी थी, उन्हीं पर जांच को प्रभावित करने का दबाव डाला गया।इससे यह साबित होता है कि जेएम फार्मा को सुनियोजित तरीके से फंसाने का प्रयास हुआ, न कि निष्पक्ष जांच के आधार पर कोई कार्रवाई।

बिना लैब टेस्ट, सीधे 'घटिया' करार!

आरटीआई दस्तावेजों के अनुसार, जेएम फार्मा की सप्लाई की गई दवाओं को बिना किसी प्रयोगशाला परीक्षण के ही घटिया घोषित कर दिया गया।रिपोर्ट पहले से तैयार थी, और जांच समिति से सिर्फ उस पर दस्तखत करवाए गए। इस तरह की कार्रवाई से न सिर्फ जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि मामले में कोई गहरी साजिश रची गई थी।

डिप्टी सीएम की कार्रवाई पर उठे सवाल

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा हाल ही में जिन अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, उन पर आरोप है कि उन्होंने जेएम फार्मा को अनुचित लाभ पहुंचाया लेकिन अब जब यह साफ हो गया है कि फार्मा को साजिशन फंसाया गया, तो फिर डॉ. नेमी की रिपोर्ट पर आधारित कार्रवाई पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

इस विरोधाभास के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है – क्या जांच समिति दबाव में थी या फिर सरकार को गुमराह किया गया?

राजेश शुक्ला, प्रोपराइटर, जेएम फार्मा

प्रेषक,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश

सेवा में,
एडवोकेट अनिल कुमार गुप्ता
कानपुर नगर

पत्र संख्या – मु०चि०अ०/2025-26/6948 दिनांक - 14/07/25

विषय - आपके द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक – 09/07/2025 के संदर्भ में।

आपके द्वारा मांगी गई सूचना के सापेक्ष क्रमबद्ध जवाब:-

1. फर्म की सभी आपूर्तियां प्राप्त हो चुकी हैं एवं प्रथम आपूर्ति के बिल सत्यापित भी हो चुके हैं।
2. सभी सामग्रियों की आपूर्ति समयावधि के अंदर हो गई थी।
3. जेम पोर्टल पर आपूर्ति हेतु समय विस्तार अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMSD स्टोर जो की जेम बायर होता है। उसकी सहमति से ओ०टी०पी० के माध्यम से विस्तार दिया जाता है।
4. 15 दिसंबर 2024 को विधानसभा सत्र के चलते कार्यालय खुला था और सभी कार्य सामान्य दिनों की तरह हो रहे थे। जिससे कार्यालय खुला होने की वजह से समय विस्तार दिया गया था।
5. आपूर्तित उन सामानों का वेरिफिकेशन हो चुका है जिनकी आपूर्ति 14 दिसंबर 2024 तक प्राप्त हुई थी। 15 दिसंबर 2024 के समय विस्तार के बाद की आपूर्ति का बिल वेरीफाई होना बाकी है।
6. उपयुक्त क्रयादेश के सापेक्ष समस्त बिल जेम पोर्टल पर अपलोड थे और बिलों की कंसाइनी रसीद और स्वीकृति प्रमाण पत्र (CRAC) जारी की जा चुकी है।
7. जेम समेकित शासनादेश संख्या - 57/18-2-2024-97(ल० उ०)/2016 दिनांक 26 नवंबर 2024 के पैराग्राफ संख्या 22 के तहत कंसाइनी रसीद और स्वीकृति प्रमाण पत्र (CRAC) जारी करने के अधिकतम 10 दिवस तक भुगतान सुनिश्चित हो जाना अनिवार्य होता है।
8. निविदा क्रय समिति के एवं जांच कमेटी के कुछ सदस्य एक ही थे।
9. उपर्युक्त अंकित कार्यदेश के सापेक्ष कुल तीन बार जांच की गई है। जो दिनांक 16 जनवरी 2025, 24 जनवरी 2025 एवं 13 फरवरी 2025 को की गई थी।
10. दिनांक 16 जनवरी 2025 को की गई जांच, जांच कमेटी द्वारा ही की गई थी और उसका निर्णय यही था कि क्योंकि आपूर्ति सामग्री लैब से संबंधित है बिना किसी उच्चस्तरीय लैब द्वारा जांच कराए बगैर सामग्री को अधोमानक नहीं कहा जा सकता।
11. 16 जनवरी 2025 की जांच आख्या तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर डॉ हरिदत्त नेमी के मन मुताबिक नहीं थी। इसी कारणवश उन्होंने दोबारा 24 जनवरी 2025 को जांच करवाई जिसमें उनके द्वारा पहले से ही बनाई गई जांच आख्या पर कमेटी से केवल हस्ताक्षर करा लिए गए थे।
12. प्रथम जांच 16 जनवरी 2025 की जांच में ही जांच कमेटी ने यह कह दिया था कि उच्चस्तरीय लैब से जांच कराए बगैर सामग्री को अधोमानक नहीं कहा जा सकता।
13. किसी भी प्रकार की जांच के लिए सामग्रियों को किसी भी लैब में नहीं भेजा गया था। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ हरिदत्त नेमी ने अपनी मंशा अनुसार जांच आख्या तैयार करी थी।
14. फर्म को किसी भी प्रकार की स्पष्ट सूचना कि किन सामग्रियों में आपत्ति है, नहीं दी गई थी।

14/7/25
ACMO (Store)
Kanpur Nagar
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कानपुर नगर

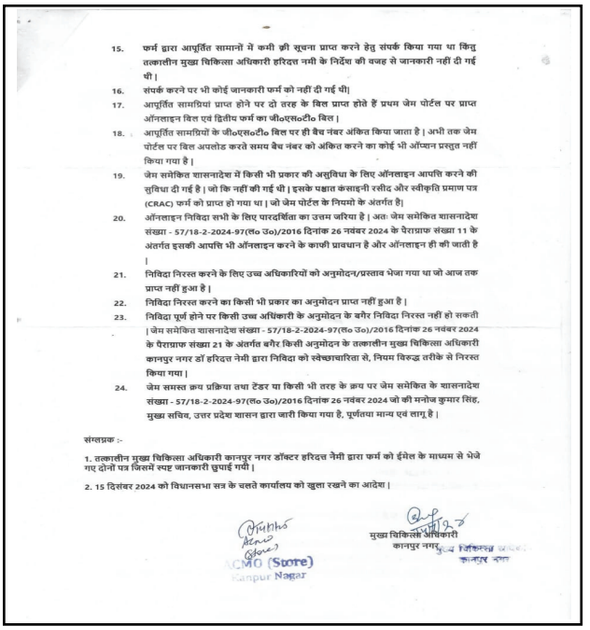

15. फर्म द्वारा आपूर्तित सामानों में कमी की सूचना प्राप्त करने हेतु संपर्क किया गया था किंतु तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिदत्त नमी के निर्देश की वजह से जानकारी नहीं दी गई थी।
16. संपर्क करने पर भी कोई जानकारी फर्म को नहीं दी गई थी।
17. आपूर्तित सामग्रियां प्राप्त होने पर दो तरह के बिल प्राप्त होते हैं प्रथम जेम पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन बिल एवं द्वितीय फर्म का जी०एस०टी० बिल।
18. आपूर्तित सामग्रियों के जी०एस०टी० बिल पर ही बैच नंबर अंकित किया जाता है। अभी तक जेम पोर्टल पर बिल अपलोड करते समय बैच नंबर को अंकित करने का कोई भी ऑप्शन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
19. जेम समेकित शासनादेश में किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए ऑनलाइन आपत्ति करने की सुविधा दी गई है। जो कि नहीं की गई थी। इसके पश्चात कंसाइनी रसीद और स्वीकृति प्रमाण पत्र (CRAC) फर्म को प्राप्त हो गया था। जो जेम पोर्टल के नियमो के अंतर्गत है।
20. ऑनलाइन निविदा सभी के लिए पारदर्शिता का उत्तम जरिया है। अतः जेम समेकित शासनादेश संख्या - 57/18-2-2024-97(ल० उ०)/2016 दिनांक 26 नवंबर 2024 के पैराग्राफ संख्या 11 के अंतर्गत इसकी आपत्ति भी ऑनलाइन करने के काफी प्रावधान है और ऑनलाइन ही की जाती है।
21. निविदा निरस्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अनुमोदन/प्रस्ताव भेजा गया था जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।
22. निविदा निरस्त करने का किसी भी प्रकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।
23. निविदा पूर्ण होने पर किसी उच्च अधिकारी के अनुमोदन के बगैर निविदा निरस्त नहीं हो सकती। जेम समेकित शासनादेश संख्या - 57/18-2-2024-97(ल० उ०)/2016 दिनांक 26 नवंबर 2024 के पैराग्राफ संख्या 21 के अंतर्गत बगैर किसी अनुमोदन के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर डॉ हरिदत्त नेमी द्वारा निविदा को स्वेच्छाचारिता से, नियम विरुद्ध तरीके से निरस्त किया गया।
24. जेम समस्त क्रय प्रक्रिया तथा टेंडर या किसी भी तरह के क्रय पर जेम समेकित के शासनादेश संख्या - 57/18-2-2024-97(ल० उ०)/2016 दिनांक 26 नवंबर 2024 जो की मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है, पूर्णतया मान्य एवं लागू है।

संलग्नक :-

1. तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर हरिदत्त नेमी द्वारा फर्म को ईमेल के माध्यम से भेजे गए दोनों पत्र जिसमें स्पष्ट जानकारी छुपाई गयी।

2. 15 दिसंबर 2024 को विधानसभा सत्र के चलते कार्यालय को खुला रखने का आदेश।

ACMO (Store)
Kanpur Nagar
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कानपुर नगर

एक ही मामले की दो तस्वीरें - कौन सही?

1. आरटीआई कहती है – जेएम फार्मा के खिलाफ साजिश रची गई।
2. कार्रवाई कहती है जेएम फार्मा को फायदा पहुंचाया गया।

फार्मा कंपनी की मांग, सीएमओ पर हो कार्रवाई

जेएम फार्मा के निदेशक राजेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए।उन्होंने यह भी कहा कि इस साजिश के चलते उन्हें भारी मानसिक, आर्थिक और व्यवसायिक क्षति हुई है।उनकी मांग है कि सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के खिलाफ भी कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए।

रिपोर्ट के आधार पर सभी कार्रवाई की गई हैं, आरटीआई में क्या जवाब दिया गया है उस संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है और यह प्रकरण कोर्ट में भी विचाराधीन है।

सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी

बरौली स्कूल के बच्चों की राह अब भी मुश्किल

रास्ते के लिए फिर उठी मांग

अब बीजेपी नेता जेपी कटियार ने दिखाई उम्मीद की किरण

» रिजवान कुरैशी, स्वराज इंडिया

बिल्हौर (कानपुर)। विकासखंड बिल्हौर के ग्रामसभा बरौली स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को अब भी पक्के रास्ते का इंतज़ार है। दो दशक पूर्व बने इस स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को अब भी कीचड़ और खेतों के बीच होकर जोखिम भरा रास्ता तय करना पड़ता है। बारिश का मौसम है हालात और भी बदतर हैं, कई बार बच्चों के फिसलकर गिरने और चोटिल होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बच बचाकर अध्यापक और अध्यापिकाएं भी किसी तरह स्कूल तक पहुंचते हैं। आपका दैनिक स्वराज इंडिया अखबार ने इस समस्या को पहले भी कई बार प्रमुखता से उठा चुका है। जिसमें तत्कालीन उपजिलाधिकारी रश्मि लाम्बा ने खबर का न केवल संज्ञान लिया। बल्कि खंड विकास अधिकारी रवी कुमार सिंह को तलब किया था और स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गई थीं। तत्कालीन एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव में चौपाल लगाई थी, लेकिन अफसोस कि उसके बाद न तो कोई कार्य योजना बनी और न ही सड़क निर्माण की दिशा में कोई कदम उठाया गया। शायद खंड शिक्षा अधिकारी भी इस समस्या पर कतई गंभीर नहीं हैं। जब भी हमारे संवाददाता ने उनसे इस विषय पर बात की, उन्होंने रटा-रटाया जवाब देकर बात को हंस कर टाल दिया जैसे यह समस्या उनकी जिम्मेदारी में ही न आती हो। हालांकि, अब एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष जय प्रकाश कटियार ने विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक को इस विषय पर पत्र लिखकर विद्यालय तक पक्के सड़क निर्माण की मांग की है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई समुचित मार्ग न होने के कारण बच्चों को कीचड़ व मेंड़ों से होकर आना-जाना पड़ता है, जिससे वे फिसलकर चोटिल हो जाते हैं। श्री कटियार ने पत्र के माध्यम से श्री पाठक से अनुरोध किया है कि संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। अब देखना होगा कि इस पत्र के बाद जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि बरौली के बच्चों की पीड़ा पर ध्यान देते हैं या एक बार फिर यह मांग पहले की तरह फाइलों में दबकर रह जाती है।

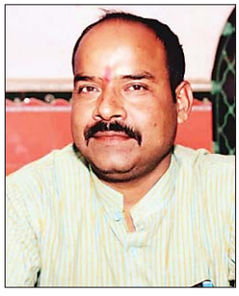

क्षेत्र की समस्याएं सुनते एमएलसी अरुण पाठक। बरौली स्कूल तक पक्के रास्ते की मांग उठाने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी कटियार।

जेपी कटियार के कदम आगे बढ़े तो फिर रुके नहीं

बिल्हौर। भाजपा नेता जेपी कटियार अपने जुझारू तेवरों के लिए पहचाने जाते हैं। वह जिस काम को हाथ में लेते हैं। उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेते हैं। यही वजह है कि राजनीति की छोटी सी सीढ़ियों से चलकर आज वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बीते दिनों जिलाध्यक्ष की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर था। लेकिन शायद कुछ लोगों की दुआएं कम पड़ गईं। जिससे उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई। लेकिन इतना तो तय है कि अपनी सेवा भावना और लोगों की दुआएं अबकी बार उनके कदम रोक नहीं पाएंगी। जिस तरह से उन्होंने स्कूली बच्चों का यह कायज़ अपने हाथों में लिया है। उसमें उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। ऐसी उम्मीद लग रही है।

बारिश में भीगती है, तालीम फैक्ट्री में चलता है स्कूल!

बिल्हौर। बारिश आई नहीं कि बरौली स्कूल के बच्चों के सपने फिर से बहने लगे। बच्चे पास की फैक्ट्री के कमरे में पढ़ते हैं। वही फैक्ट्री जहां कभी मशीनें गरजती थीं। स्कूल तक पहुँचने का रास्ता कीचड़ में तब्दील है,जिसमें नन्हे कदम फिसलते हैं,सपने धँसते हैं।सरकारी काग़ज़ों में स्कूल है,पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बरसात में ये स्कूल किसी खतरे से कम नहीं। पास की फैक्ट्री में स्कूल संचालित होना खुद में एक सवाल है, कि शिक्षा की ये इमारत आखिर कब अपनी ज़मीन और पहचान पाएगी।

...और अब शर्मिंदा नहीं, सवालों में हूँ!

बिल्हौर। मैं बरौली स्कूल हूँ.. मैंने आज़ादी के बाद जन्म लिया,पर अब तक आज़ादी की बुनियादी ज़रूरत, एक रास्ता तक नहीं देख पाया। बारिश में मुझ तक पहुँचना किसी मुसीबत से कम नहीं। ज्यादा बारिश होने पर मेरे स्कूल के बच्चे पास की एक फैक्ट्री के कमरे में पढ़ते हैं,जहां न उजाला है, न सुरक्षा और न ही सम्मान। मैं पूछता हूँ...क्या बच्चों की तालीम इतनी सस्ती है.. मैं पूछता हूँ...रास्ता बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या बरौली के बच्चों को पक्की सड़क का हक नहीं? नेताओं को फर्क क्यों पड़ेगा...उनके बच्चे तो बड़ी गाड़ियों में बैठकर एसी स्कूलों तक जाते हैं। मैं बरौली स्कूल हूँ...अब चुप नहीं रहूँगा। जब तक रास्ता नहीं बनेगा। मैं हर सुबह सवाल बनकर खड़ा रहूँगा।

आफत

स्कूल से लेकर घर-बाजार तक लोग गर्मी और उमस की मार से परेशान हुए

बेवफा बिजली...देर रात लौटी, वो भी रूठ-रूठ कर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर वासियों की गुरुवार की सुबह जैसे ही आंख खुली, बिजली आंखों से ओझल हो गई। फिर जो गई, तो देर रात तक किसी महबूबा की तरह इंतजार करवाती रही। एक-आध बार आई भी तो ऐसे जैसे कोई रूठी प्रेमिका दीवार के पीछे से झांकती हुई आई, टिमटिमाई और चली गई।

पूरा दिन बिल्हौर टाउन पसीने में डूबा रहा। स्कूल से लेकर घर और बाजार तक गर्मी की मार ऐसी कि सबका फाल्ट लेवल हाई हो गया। ऊपर से अफसरों के फोन स्विच ऑफ़.. और जनता का धैर्य ऑन... हर घंटे बस यही जवाब मिला..थोड़ी देर में आ रही है, मगर बिजली मोहतरमा शहर के नजदीक तक नहीं भटकी। जब इंतजार बेसब्री में बदला, तो वकील, भाजपा नेता और स्थानीय नागरिकों का प्रतिनिधि मंडल बिजली घर पहुंच गया। वहां सवालों की बौछार हुई, मगर अफसरों के पास न जवाब थे, न तैयारी, सिर्फ चुप्पी। रात करीब 9 बजे टाउन के जेई से बात की तो उन्होंने बताया कि दो टेस्ट बॉक्स में तकनीकी फॉल्ट था। बाहर से टेक्नीशियन बुलाने पड़े, मरम्मत के बाद ही लाइन बहाल हो सकी।

» सुबह से गई बिजली ने रात तक आने का नाम नहीं लिया

» बाहर से टेक्नीशियन बुलाने पड़े तब बहाल हो सकी लाइन

सम्पादकीय

पंजाब में बढ़ते अपराध गंभीर चुनौती

एक बार फिर पंजाब देश-विदेश से संचालित आपराधिक गैंगों और आतंकवादियों के निशाने पर आ गया है। संगठित आपराधिक गिरोहों द्वारा आम-खास लोगों को शिकार बनाये जाने की घटनाएं जब-तब सामने आती रहती हैं। हाल ही में एक पृथकतावादी संगठन के सक्रिय आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया का अमेरिका से प्रत्यर्पण इस बात की याद दिलाता है कि राज्य में चरमपंथी विचारधारा का साया कितना गहरा बना हुआ है। आरोप है कि करीब चौदह ग्रेनेड हमलों को अभियुक्त ने अंजाम दिया। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले अभियुक्त पासिया की भारत वापसी निस्संदेह आगे की जांच में मददगार साबित होगी। इससे भारत विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों के काले अध्याय फिर सामने आने की भी उम्मीद जगी है। इस प्रकरण के उजागर होने से एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि कैसे पंजाब को भारत विरोधी ताकतों द्वारा विदेशों से निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य में गैंगस्टरों द्वारा की जा रही हिंसा में खतरनाक ढंग से वृद्धि देखी जा रही है। अबोहर के व्यवसायी संजय वर्मा की दिनदहाड़े हुई हत्या और मोगा में अभिनेत्री तानिया के डॉक्टर पिता की उनके क्लीनिक में गोली मारकर की गई निर्मम हत्या ने इस बात को उजागर किया कि संगठित आपराधिक नेटवर्क कितनी आसानी से काम कर रहे हैं। हमलावरों द्वारा सार्वजनिक रूप से मरीज बनकर डाक्टर को गोली का निशाना बनाना आपराधिक दुस्साहस को ही उजागर करता है। जो बताता है कि अपराधियों में कानून व पुलिस का खौफ नजर नहीं आता। यह समाज वैज्ञानिकों के लिये भी गंभीर मंथन का विषय है कि राज्य का समाज इस गहरी अस्वस्थता का शिकार क्यों है। निश्चित रूप से समाज में आर्थिक विसंगतियां और सामाजिक विद्रूपताएं अपराध की राह खोल रही हैं। वहीं दूसरी ओर, राज्य में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी, नशे की लत, अशांत बचपन, गरीबी, विषैली राजनीति और रातों-रात अमीर बनने की लालसा कई पंजाबी युवाओं को अपराध की अंधी गली की ओर धकेल रही है। ऐसा भी नहीं है कि बेरोजगारी व अन्य सामाजिक विसंगतियां देश के अन्य राज्यों में नहीं हैं। नशा एक राष्ट्रीय संकट बनता जा रहा है।

सवाल ये कि हमारा शासन-प्रशासन इन अपराधों से किस तरह निबटता है। विडंबना यह भी है कि सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा में गैंगस्टरों का महिमामंडन आग में घी डालने का काम कर रहा है। निस्संदेह, अपराध का रास्ता कई युवाओं को आकर्षित करता है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि इस राह से गुजरने के बाद मुख्यधारा में लौटना असंभव है। अपराधी फिर कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकता। लेकिन इसके बावजूद शासन-प्रशासन को राज्य में उन सामाजिक-आर्थिक विसंगतियों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की सख्त जरूरत है, जो अपराध को बढ़ावा देते हैं। उन विभागीय काली भेड़ों की भी सख्त निगरानी की जरूरत है जो अपराधियों के अपवित्र गठबंधन में मददगार होती हैं। हालांकि, पंजाब पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां और मुठभेड़ें की हैं, लेकिन ये महज एक प्रतिक्रियात्मक कदम मात्र है। इस बड़े संकट से निपटने के लिये एक निरंतर, व्यवस्थित व कारगर रणनीति बनाने की जरूरत है। वहीं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत बनाने की दरकार है। इसके साथ ही शिक्षा प्रयासों का विस्तार करने, पुनर्वास और न्यायिक प्रक्रियाओं को भी तेज करने की आवश्यकता है।

ठोस रणनीति से ही हिमाचल में नशा मुक्ति की राह

सोमेश गोयल

हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की समस्या बड़ी चुनौती बन गयी है। सिंथेटिक ड्रग्स की स्मगलिंग गंभीर समस्या है। शिकंजा कसने के लिए नशा निवारण कानून के तहत पुलिस द्वारा दर्ज मामले बढ़े हैं। राज्य में एक सर्वेक्षण जरूरी है जिससे नशे के आदी लोगों की पहचान व ठोस रणनीति के तहत पुनर्वास का सतत अभियान चलाया जा सके। इस माफिया पर नकेल के लिए वित्तीय जांच भी बढ़ाई जाये।हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से एक सशक्त संदेश देते हुए पुलिस ने केवल एक महीने में ही 250 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ नशा तस्करी के आरोप में मुकदमें दर्ज किए हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 183 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

प्रदेश में 14 मामले वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ रखने के लिए, 85 मामले मध्यम मात्रा के लिए और 58 मामले छोटी मात्रा के लिए दर्ज किए गए। लगभग दो दर्जन मामले नशीली दवाओं की खेती से संबंधित थे। एक सकारात्मक कदम के रूप में पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 21 निवारक प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू की है। राज्य पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से आधा दर्जन आदेश प्राप्त करने में भी सफलता हासिल की है। लगभग तीन दशकों से मादक पदार्थों की समस्या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तस्करी ने केवल गांजा केंद्रित व्यापार से बदलकर छिपाने में आसान और उच्च कीमत वाले सिंथेटिक ड्रग्स की स्मगलिंग का रूप ले लिया है। दूरदराज व दुर्गम इलाके का फायदा उठाते हुए अपराधी यहां अफीम की अवैध खेती भी करते हैं।

वर्ष 2019 के नशीले पदार्थों के उपयोग संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश के लिए कोई गंभीर चेतावनी नहीं दी गयी थी। हालांकि, तब से काफी कुछ बदल चुका है। समस्या की सटीक स्थिति जानने के लिए राज्य स्तर पर एक नमूना सर्वेक्षण की तत्काल आवश्यकता है। पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में 41 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। राज्य के लिए चिंताजनक बात यह है कि मादक पदार्थों के मामलों में गिरफ्तार किए गए 90 प्रतिशत से अधिक लोग 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के हैं। राज्य की जेलों में लगभग तेरह सौ युवा मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में बंद रहते हैं। राज्य का कोई भी जिला मादक पदार्थों की समस्या से अछूता नहीं है। शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में इस श्रेणी के अधिकतम मामले दर्ज होते हैं।

राज्य की जेलों में एनडीपीएस मामलों से जुड़े दोषी और अभियुक्त कैदियों की संख्या अधिक है। लगभग 40 प्रतिशत पुरुष कैदी, चाहे दोषी हों या अभियुक्त, मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में शामिल हैं। महिलाओं के लिए यह आंकड़ा लगभग 30 प्रतिशत है। छोटी मात्रा के तस्कर अक्सर स्वयं भी नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। लगभग 10 प्रतिशत कैदियों को नशामुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों का स्थान जेल नहीं बल्कि पुनर्वास केंद्र होना चाहिए। पुनर्वास के लिए कोई भी तय प्रोटोकॉल न होने के कारण, सुधार गृहों में तैनात चिकित्सक मादक पदार्थों के उपयोगकर्ताओं के उपचार में दक्ष हो गए हैं। राज्य के सुधार विभाग का प्रयास, जो एक केंद्रीय जेल में पुनर्वास केंद्र शुरू करने के लिए एक केंद्रीय योजना का लाभ उठाना चाहता था, राज्य सरकार के एक बाबू द्वारा खारिज कर दिया गया! राज्य सरकार को उन सभी सुधार गृहों को, जहां समर्पित चिकित्सक तैनात हैं, औपचारिक रूप से मादक पदार्थ पुनर्वास केंद्र घोषित करना चाहिए।राज्य की मादक पदार्थ समस्या के प्रति प्रतिक्रिया अब तक टिकाऊ नहीं रही है, जिसने संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले, राज्य सीआईडी के तहत एक एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) स्थापित की गई। बाद में, एक राज्य कानून पारित किया गया और एक विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) बनाई गई, लेकिन एएनटीएफ को समाप्त नहीं किया गया।

संतुलित समाज के निर्माण में हो सहायक

पुरुष आयोग की मांग

डा0 सुधीर कुमार

तर्क दिया जा रहा है कि पुरुष आयोग बनाना समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों को भी उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। यह एक ऐसी संस्था होगी जो पुरुषों से संबंधित डेटा एकत्र करेगी, उनकी शिकायतों को सुनेगी, और सरकार को उनके कल्याण के लिए सुझाव देगी।जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, तो अक्सर महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तीकरण पर ज़ोर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही और आवश्यक भी है।

यह लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम है। समाज में लिंग-आधारित रूढ़िवादिता के कारण, पुरुषों को अपनी पीड़ा व्यक्त करने में हिचकिचाहट होती है, जिससे उनकी समस्याएं अक्सर अनसुनी रह जाती हैं।लंबे समय से, घरेलू हिंसा और प्रेम संबंधों में होने वाली क्रूरता को अक्सर महिलाओं से जोड़कर देखा जाता रहा है, जो कि बिल्कुल सही भी है। महिलाएं इन अपराधों का शिकार होती हैं। लेकिन, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि पुरुष भी इन अपराधों के शिकार हो रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां प्रेम संबंधों में अनबन या अन्य कारणों से पतियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है।उनके पास मदद या शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई खास मंच नहीं है।झूठे आरोप भी एक गंभीर समस्या है जिससे पुरुष जूझते हैं। दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या अन्य अपराधों के झूठे आरोप पुरुषों के जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं, भले ही वे बाद में निर्दोष साबित हो जाएं। यह उनके करिअर, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। वर्तमान कानूनी ढांचे में, ऐसे मामलों में पुरुषों को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अक्सर लंबा और जटिल संघर्ष करना पड़ता है, और उनके लिए कोई विशेष सहायता प्रणाली नहीं है।

इसके अलावा, दहेज उत्पीड़न या बलात्कार जैसे कानूनों का कई बार दुरुपयोग होता है, जिसके चलते कई निर्दोष पुरुषों को झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है। पारिवारिक विवादों, जैसे तलाक या बच्चों की कस्टडी के मामलों में भी, अक्सर पुरुषों को अलग-थलग महसूस कराया जाता है और उनके पक्ष को कई बार उचित महत्व नहीं मिलता। मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है ; समाज का दबाव पुरुषों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में उन्हें न्याय पाने और अपनी बेगुनाही साबित करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह उनके करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है।

समाधान दिवसों के लिए डीएम ने जारी किया रोस्टर

» हर माह दो शनिवार को होगी जनसुनवाई

» जन शिकायतों को बेहतर तरीके से सुलझाने के लिए डीएम कर रहे हैं प्रयास

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। जिले में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की अध्यक्षता का रोस्टर गुरुवार को जारी कर दिया है। यह समाधान दिवस हर माह के पहले और तीसरे शनिवार को सभी तहसीलों में आयोजित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समाधान दिवसों में अधिकारी समय से उपस्थित रहें और जनसुनवाई को गंभीरता से लेकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।

प्रशासन के अनुसार, जनवरी 2026 तक का समाधान दिवस रोस्टर पहले ही निर्धारित कर दिया गया है, ताकि कार्यों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तय किया जा सके। समाधान दिवस शासन की प्राथमिक योजनाओं में शामिल है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आम जनता अपनी शिकायतों को सीधे अधिकारियों के समक्ष रखती है।

जारी रोस्टर के अनुसार, आगामी समाधान दिवसों में विभिन्न तहसीलों में जन सुनवाई की अध्यक्षता इस प्रकार होगी

2 अगस्त 2025 (शनिवार)
तहसील सदर-जिलाधिकारी
नर्वल -एडीएम (वित्त)
घाटमपुर-एडीएम (आपूर्ति)
बिल्हौर- एडीएम (न्यायिक)

16 अगस्त 2025 (शनिवार)
सदर -एडीएम (सिटी)
नर्वल -जिलाधिकारी
घाटमपुर-एडीएम (आपूर्ति)
बिल्हौर- एडीएम (न्यायिक)

6 सितंबर 2025 (शनिवार)
सदर -एडीएम (सिटी)
नर्वल -एडीएम (वित्त)
घाटमपुर -जिलाधिकारी
बिल्हौर ० एडीएम (न्यायिक)

20 सितंबर 2025 (शनिवार)
सदर -एडीएम (सिटी)
नर्वल - एडीएम (वित्त)
घाटमपुर -एडीएम (आपूर्ति)
बिल्हौर - जिलाधिकारी

अवैध निर्माण पर केडीए की बड़ी कार्रवाई, 4 निर्माण सील

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। विकास प्राधिकरण (केडीए) के उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्यांयाल के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चार परिसरों पर सील की कार्रवाई की है। कार्रवाई प्रवर्तन जोन-2 के तहत जोनल प्रभारी संदीप मोदनवाल की अगुवाई में की गई।

इन निर्माण स्थलों पर प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति लिए बिना अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था। इस पर प्रभारी अधिकारी व अवर अभियंता रमाकान्त की मौजूदगी में प्रवर्तन दल ने कार्रवाई करते हुए भवनों को सील किया।केडीए ने जानकारी दी है कि प्रवर्तन क्षेत्र में चल रहे अन्य अवैध निर्माणों की पहचान कर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि निर्माण से पहले सभी

वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करें, अन्यथा सख्त दंडात्मक कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है।

इन पर हुई सीलिंग की कार्रवाई

1. श्री उत्कर्ष कटियार व अन्य ङ्क प्लॉट संख्या 167-०आराजी संख्या 115/02, कल्याणपुर खुर्द, न्यू शिवली रोड
2. श्री गौरव मिश्रा - आराजी संख्या 1647 व 1650, बारासिरोही, कल्याणपुर
3. श्री विजय कुमार कटियार -प्लॉट संख्या 117/02, ब्लॉक-एन, काकादेव
4. श्री राजीव सब्बरवाल पुत्र स्व. रल्लाराम सब्बरवाल - भवन संख्या 117/॥-2, 78 (प्लॉट संख्या-395), काकादेव

फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर ठगी की कोशिश, 10 हजार रुपये की मांगसाइबर सेल में शिकायत, पुलिस ने शुरू की जांच

स्वराज इंडिया न्यूज यूरो

कानपुर। कल्याणपुर के सत्यम बिहार में एक युवक के साथ फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़ित शुभम चौधरी, जो निजी नौकरी करता है, ने बताया कि गुरुवार सुबह एक अनजान नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आई। फोन उठाते ही कॉलर ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और आरोप लगाया कि शुभम अश्लील वीडियो देखता है, जिसके चलते लखनऊ में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

शुभम के मुताबिक, वह इस बात से घबरा गया और फोन अपने बड़े भाई को दे दिया।

कॉलर ने भाई से कहा—अगर अपने भाई की इज्जत बचाना चाहते हो तो तुरंत 10 हजार रुपये पेटीएम करो। जब भाई ने मुकदमे की जानकारी और थाने का नाम पूछना चाहा तो कॉलर ने गाली-गलौज करते हुए फोन काट दिया और धमकी दी कि 卐अब पुलिस खुद घर आकर बताएगी कि केस कहां दर्ज है।卐

घटना से परेशान शुभम ने तत्काल साइबर सेल में शिकायत की। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है।

पुलिस ने आम जनता को सतर्क करते हुए कहा है कि कोई भी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर इस तरह धमकाए तो उसकी तुरंत सूचना 112 या साइबर हेल्पलाइन नंबर पर दें।

आवश्यक सूचना

मैं शाहिद पुत्र शकूर यह सार्वजनिक रूप से सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र शाहिल (उम्र 26 वर्ष), शीबू (उम्र 20 वर्ष) व पुत्रवधू जहेरा (पत्नी शीबू) का चाल-चलन ठीक नहीं है। ये लोग आए दिन गाली-गलौज व मारपीट कर मानसिक तनाव उत्पन्न करते हैं।इस कारण मैं इन्हें अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ। आज से मेरा व मेरे परिवार का इनसे कोई लेन-देन, संबंध या सरोकार नहीं रहेगा। ये अपने अच्छे-बुरे के स्वयं जिम्मेदार होंगे।

शाहिद पुत्र शकूर
निवासी- नई बस्ती सुभानपुर मुरादनगर,
थाना व तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर ।

कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। भारतीय राजनीति के चाणक्य और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से कानपुर के लोकप्रिय सांसद रमेश अवस्थी ने शिष्टाचार भेंट की।

इस भेंट के दौरान सांसद अवस्थी ने कानपुर व आसपास के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों, जनहित के मुद्दों और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त कर उनके अनुभवों से लाभान्वित होने का अवसर भी प्राप्त किया।

श्री शाह ने सांसद अवस्थी को आवश्यक सहयोग व समर्थन का आश्वासन देते हुए जनसेवा की भावना से कार्य करते रहने की प्रेरणा दी। यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दीनू के मददगार दो कथित पत्रकारों की भी जांच शुरू

» कुछ चौकी इंचार्जों और थानेदारों की भी हो रही पड़ताल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर में बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या में सोनभद्र जेल में बंद धीरज उर्फ दीनू उपाध्याय के मददगार दो और कथित पत्रकारों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर दीनू के साथियों की मदद करने का आरोप है। उनके आर्थिक स्रोत की एलआईयू के स्टाफ से रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है जिसमें प्लॉट, घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। कुछ चौकी इंचार्जों और थानेदारों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दो वादियों ने जानकारी दी थी कि उन्होंने जब कब्जे की शिकायत की तो उनसे कुछ लोगों ने संपर्क किया था, वे खुद को पत्रकार बता रहे थे। उन लोगों ने दीनू के साथियों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें की थीं। वे लोग वादी को डरा रहे थे। ऐसे कथित पत्रकारों के दीनू के कुछ साथियों से मोबाइल पर बातचीत होने के सबूत मिले हैं। उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। इनके भूमाफिया से भी संपर्क होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जांच के लिए क्राइम ब्रांच और एलआईयू के विशेष स्टाफ लगाए गए हैं।मंगलवार को ही पुलिस ने दीनू उपाध्याय गैंग के सक्रिय सदस्य दीपक जादौन समेत 48 शातिरों की हिस्ट्रीशीट खोली है। इससे पहले सोमवार को गैंग के दूसरे सदस्य अधिवक्ता नारायण भदौरिया की हिस्ट्रीशीट किदवईनगर पुलिस ने खोली थी। इसके अलावा रेउना थाने से किरांव गांव निवासी विजय प्रताप सिंह उर्फ कल्ली की हिस्ट्रीशीट खुली है। वह हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने, छेड़खानी आदि का आरोपी है। गोविंदनगर से धोखाधड़ी के आरोपी प्रापर्टी डीलर गुरमीत सिंह, शरद पासवान समेत नौ और बर्रा से अभिषेक शर्मा, दीपक कनौजिया समेत सात लोग शामिल हैं जबकि किदवईनगर से यूट्यूबर अनुज जैन की हिस्ट्रीशीट खुली है।

ब्राह्मणों के खिलाफ साजिश या पुलिसिया मनमानी? मंत्री के धरने से सियासत गर्म

» बदलापुर विवाद: मंत्री के पति की चेतावनी डिप्टी सीएम बताए क्या करें, फांसी लगाएं?

» इंस्पेक्टर पर फर्जी मुकदमे का आरोप, छह घंटे धरने पर बैठीं राज्य मंत्री

» थाने में मंत्री, फोन पर पूर्व सांसद डिप्टी सीएम से मांगा ब्राह्मणों का सुरक्षा प्रमाणपत्र

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। बदलापुर में सड़क निर्माण विवाद के बाद भाजपा कार्यकर्ता पर दर्ज एफआईआर ने सियासी भूचाल ला दिया। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला गुरुवार को अकबरपुर कोतवाली पहुंचीं और धरने पर बैठ गईं। उन्होंने थानेदार सतीश सिंह पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया और उन्हें हटाने की मांग की। मंत्री के धरने के चलते देर शाम पुलिस कप्तान खुद थाने पहुंचे और लालपुर चौकी प्रभारी को लाइनहाजिर कर इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। तब जाकर करीब छह घंटे बाद मंत्री ने धरना समाप्त किया।

अगर ब्राह्मण सुरक्षित नहीं, तो रस्सी लाओ, फांसी पर लटक जाए'

धरना दे रही मंत्री के साथ उनके पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी भी मौजूद थे। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से फोन पर बात करते हुए भावुक होकर कहा, आप तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अगर हमारी ही सुरक्षा नहीं हो सकती, तो बताइए हम राजनीति छोड़ दें या फांसी पर लटक जाएं? फोन कटने के बाद उन्होंने समर्थकों से कहा, रस्सी लाओ, यहीं फांसी लगा लेते हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

सड़क निर्माण बना विवाद की जड़, दो पक्ष आमने-सामने

मामला अकबरपुर नगर पंचायत के बदलापुर इलाके का है, जहां विधायक निधि से सड़क बन रही थी।

स्थानीय सभासद शमशाद ने निर्माण को गलत बताते हुए काम रुकवा दिया। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद निर्माण दोबारा शुरू हुआ, जिससे ठेकेदार जहूर की तहरीर पर शमशाद के खिलाफ रंगदारी और काम में बाधा का मुकदमा दर्ज हुआ। इसी घटनाक्रम के बाद बदलापुर गांव निवासी बाबूराम की तहरीर पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष शिवा पांडेय सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिससे मंत्री नाराज हो गईं और थाने का घेराव कर दिया।

इस घटना से स्पष्ट है कि प्रशासनिक कार्यशैली और राजनीतिक हस्तक्षेप के टकराव में सबसे बड़ा नुकसान आम जन को ही उठाना पड़ता है।

धन गबन के आरोप में प्रधान के अधिकार सीज, सचिव निलंबित

» जिला अधिकारी की सख्त कार्रवाई, 7.50 लाख रुपये की अनियमितता उजागर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। देवराहट ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी के मामले में जिलाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम प्रधान शकुंतला देवी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। साथ ही तत्कालीन ग्राम सचिव सचिन रस्तोगी को निलंबित कर दिया गया है।

जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पंचायत में गलत बिल-वाउचर के माध्यम से ?7,50,689 की राशि का गबन किया गया। इस पर कार्यवाही करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी विकास पटेल ने संबंधित जेई रूप सिंह से भी स्पष्टीकरण तलब किया है। मजरा जारी के निवासी महाराज सिंह ने 21 मई 2022 को डीएम को शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान के खिलाफ हैंडपंप रिबोर सहित अन्य विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत की थी। इसके बाद डीपीआरओ द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक, परियोजना प्रबंधक और ग्रामीण मौजूद रहे।

निरीक्षण में आरोप सही पाए गए, और सात लाख पचास हजार से अधिक की वित्तीय अनियमितता सामने आई।

विकास कार्य प्रभावित न हों - प्रशासन सक्रिय

तीन स्तरों पर कार्रवाई

ग्राम प्रधान शकुंतला देवी — वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज

सचिव सचिन रस्तोगी — निलंबन

जेई रूप सिंह (आरईडी) — गलत एमबी भरने पर जवाब तलब

डीपीआरओ विकास पटेल ने बताया कि ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गांव के विकास कार्यों को बाधित न होने देने के लिए जल्द ही तीन सदस्यीय टीम गठित की जाएगी।

जिलाधिकारी आलोक सिंह ने कहा, सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

यह कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

लिपिक की लापरवाही से शिक्षक परेशान, संगठन ने सौंपा ज्ञापन

» एरियर और वेतनमान अटका, शिक्षकों ने लगाया सुविधा शुल्क मांगने का आरोप

» खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विकासखंड मलासा के अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संगठन ने गुरुवार को शिक्षक हितों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और कार्यालय में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी के लिपिक की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए 6 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।

ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सचान के नेतृत्व में शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी आनंद भूषण को ज्ञापन सौंपते हुए

कहा कि 29 जनवरी 2024 को कई शिक्षकों की चयन वेतनमान से जुड़ी पत्रावलियां जमा होने के बावजूद अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है।

शिकायतें पुरानी, सुनवाई नहीं

आरोप है कि लिपिक सुविधा शुल्क लेकर करता है चयनित फीडिंग शिक्षक उपेन्द्र कुमार की वेतन बिल पत्रावली पर 4 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अरुण झा, रामनरेश, रविन्द्र कुमार, और पूजा सचान सहित कई अन्य शिक्षकों के एरियर और चयन वेतन से संबंधित पत्रावलियां 23 मई 2025 को लिपिक को दी गई थीं, लेकिन दो माह बाद भी कोई अपडेट नहीं मिला। शिक्षकों का आरोप है कि दो मामलों में सुविधा शुल्क लेकर फीडिंग की गई, जबकि अन्य मामलों में जानबूझकर टालमटोल किया जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने लिपिक के खिलाफ अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। खंड शिक्षा अधिकारी आनंद भूषण ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई और जांच का आश्वासन दिया है। इस मौके पर जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष सर्वेश कटियार, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत यादव, सतेन्द्र कुमार मिश्रा, अंशिका कटियार, सुजीत सिंह समेत कई शिक्षक उपस्थित रहे।

राजपुर ब्लॉक खुद पानी को तरसा, विकास के दावों पर उठे सवाल

» हैंडपंप सूखा, आरओ खराब ब्लॉक परिसर में बूंद-बूंद को मोहताज लोग

» अफसरों की चुप्पी, जनता की बेबसी गांवों में व्यवस्था की हकीकत उजागर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर ब्लॉक मुख्यालय में पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी अब एक 'सुविधा' बनकर रह गई है। यह वही ब्लॉक है, जहां से सरकारी योजनाओं की नीतियां बनती हैं, फाइलें चलती हैं और गांवों को विकास का सपना दिखाया जाता है। लेकिन चुनौती बन गई है पानी कहां से पिएं? ब्लॉक में हर दिन सैकड़ों ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, बीडीसी और अन्य लोग अपने कार्यों से आते हैं। मगर गर्मी से बेहाल यह लोग या तो पास के गांव में किसी के घर जाकर पानी मांगते हैं, या फिर प्यासे ही लौट जाते हैं। ब्लॉक में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी तो अपने लिए पानी की बोतल घर से लेकर आते हैं या कार्यालयों में रखते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। यह एक ऐसी असंवेदनशीलता है, जो प्रशासन की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है।

बीडीओ और एडीओ पंचायत ने दिखाया पल्ला झाड़ने वाला रवैया

हकीकत यह है कि यह ब्लॉक खुद पानी के लिए तरस रहा है। ब्लॉक परिसर में स्थित हैंडपंप कई दिनों से खराब पड़ा है। यही नहीं, जो आरओ वाटर कूलर कभी ग्रामीणों और कर्मचारियों की प्यास बुझाता था, वह भी अब शो-पीस बनकर रह गया है। इस भीषण गर्मी में यहां आने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी

जब इस विषय में राजपुर के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) से पांच बार संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। यह दर्शाता है कि जिम्मेदार अफसर खुद समस्या से मुंह मोड़ रहे हैं। वहीं, एडीओ पंचायत से इस समस्या पर जवाब मांगा गया, तो उन्होंने गोलमोल बात करके अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर ब्लॉक मुख्यालय का ये हाल है, तो गांवों की स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं। जब योजना संचालित करने वाला संस्थान ही अव्यवस्था का शिकार हो, तो ग्रामीण इलाकों में विकास की उम्मीद करना कितना तर्कसंगत है?

नाबालिग को भगाने का आरोप, युवक पर मुकदमा दर्ज

» आरोपी ने फोन कर खुद दी जानकारी, बोला शादी करा दीजिए

» बरौर थाना पुलिस ने किशोरी और आरोपी की तलाश शुरू की

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र में एक युवक पर नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगा है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी समेत आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता के पिता ने गुरुवार को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे उनकी नाबालिग बेटी अपने बाबा के घर पर थी। तभी भोगनीपुर थाना क्षेत्र के गुरगांव, हाल निवासी ग्राम मकरंदापुर थाना बरौर का युवक

सागर सचान उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे सागर ने अपने मोबाइल फोन से कॉल कर पिता को जानकारी दी कि किशोरी उसके साथ है और बोला मुझसे उसकी शादी करा दीजिए।थानाध्यक्ष अमिता वर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और किशोरी व आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है।

कामयाबी

लोहिया संस्थान ने रचा इतिहास

लेजर एंजियोप्लास्टी से चार मरीजों की नसों को दी नई जिन्दगी

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। लखनऊ स्थित डॉ. राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने हार्ट मरीजों के इलाज में बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए उत्तर भारत का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां लेजर एंजियोप्लास्टी तकनीक से सफल इलाज किया गया।

संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग में चार मरीजों की कोरोनरी एंजियोप्लास्टी लेजर तकनीक से की गई। इनमें से दो मरीजों के पुराने स्टंट में कैल्सियम जमने और सिकुड़ने की समस्या थी, जिसे लेजर से साफ कर दोबारा स्टंटिंग की गई। यह तकनीक अब तक भारत के सिर्फ कुछ चुनिंदा संस्थानों में ही मौजूद है।

लेजर एंजियोप्लास्टी एक उन्नत और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल, या कैल्सियम को लेजर की मदद से तोड़ा जाता है। यह उन मरीजों के लिए वरदान मानी जाती है, जिनकी पारंपरिक एंजियोप्लास्टी असफल हो चुकी होती है और जिन्हें बाइपास सर्जरी का सुझाव दिया जाता है हालांकि, यह प्रक्रिया सामान्य एंजियोप्लास्टी की तुलना में थोड़ी महंगी है और उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता की मांग करती है।

इस जटिल प्रक्रिया को अंजाम देने वाली विशेषज्ञ टीम में शामिल रहे-

प्रो. सुदर्शन कुमार विजय, प्रो. अमरेश सिंह, डॉ. अभिजीत, डॉ. शिखर, डॉ. सैयद अकरम सहयोग में थे पैरामेडिकल स्टाफ प्रियरंजन, कर्णिका, और नर्सिंग स्टाफ शैलजा व अजय।

बताया गया है कि लेजर मशीन चेन्नई से मंगाई गई और फिलहाल पोर्टेबल मशीन से सेवा दी जा रही है।

एंजियोप्लास्टी क्या है?

एंजियोप्लास्टी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें हृदय की अवरोधित धमनियों को खोला जाता है। इसमें एक छोटा मेडिकल बैलून अवरुद्ध हिस्से में जाकर प्लाक को हटाता है। यह प्रक्रिया बाइपास सर्जरी की

तुलना में कम आक्रामक मानी जाती है और मरीज को जल्द राहत देती है।

क्यों खास है ये उपलब्धि?

उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला सरकारी संस्थान जहां लेजर तकनीक से इलाज हुआ।जटिल मामलों में बाइपास सर्जरी से बचा जा सकता है।

मरीजों के लिए कम दर्दनाक और तेजी से ठीक होने वाली प्रक्रिया।

इस तकनीक के शुरू होने से अब हृदय रोगियों को इलाज के लिए अन्य बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लखनऊ के लोहिया संस्थान ने एक बार फिर प्रदेश को चिकित्सा के क्षेत्र में गौरवान्वित किया है।

सदर तहसील: रिश्वत की तह में दबा इंसाफ

» सदर तहसील में घूसलोक- बिना दक्षिणा के नही होती दाखिल खारिज!

» यहां कानूनगो नही कैशनोगो बैठते है!

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश और तमाम सख्तियों के बावजूद सदर तहसील में भ्रष्टाचार का डंका बज रहा है। यहां लेखपालों से लेकर कानूनगो और अधिकारी तक, सबने मानो रिश्वत को फ्नियमफ् बना लिया है। मामूली दाखिल-खारिज से लेकर भूमि विवादों तक बिना सुविधा शुल्क दिए एक पन्ना भी आगे नहीं बढ़ता।

ताजा रिपोर्टों के अनुसार, अब तक आधा दर्जन से अधिक राजस्वकर्मी निलंबित या गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनके ठिकानों पर जमे दलाल और छुटभैये सिस्टम को फिर से पटरी पर ला देते हैं।

विगत तहसील दिवस पर आई 100 से अधिक शिकायतों में से केवल 5 का निस्तारण यह दिखाने के लिए काफी है कि अफसरों की नीयत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं।

शिकायतकर्ता इधर-उधर भटकते रहे और अंदर भुगतान करने वालों के काम फटाफट निपटते रहे।

जमीन के नाम पर खुला बाजार

राम मंदिर के फैसले के बाद अयोध्या में जमीनों की कीमतों में आए उछाल ने सदर तहसील को 'कमाई का हॉटस्पॉट' बना दिया है। सूत्रों की माने तो जमीन से जुड़े हर दस्तावेज़ पर 5000 से 40000 प्रति बिस्वा तक की वसूली हो रही है। बयान के लिए आओ, फिर जांच के नाम पर दौड़ाओ यही नियम है।

दलालों का सिंडिकेट

अब यह साफ दिखता है कि तहसील कार्यालय में बिना दलाल के प्रवेश भी कठिन है। ये दलाल फर्जी कागजात से लेकर सरकारी जमीन पर कब्जे तक के सौदे करवा रहे हैं। अधिकारी जानते हुए भी आँखें मूंदे हुए हैं।

बाग विजेशी मामला- सीधा घोटाला, ढकी जांच

हाल ही में चर्चित बाग विजेशी मामले में फर्जी पत्रों के आधार पर सरकारी जमीन बेच दी गई। जब मीडिया में शोर मचा, तो एफआईआर दर्ज हुई, आदेश निरस्त भी हुआ लेकिन कार्रवाई? अब भी ठंडे बस्ते में।

राजस्व विभाग की कार्यशैली से नाराज़ एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता ने सीधे योगी सरकार की छवि पर सवाल उठाते हुए कहा, ये कर्मचारी नहीं, पूरे सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं।

सदर तहसील अब केवल जमीन का नहीं, जनता के भरोसे के चीरहरण का केंद्र बन चुकी है।

अगर इस भ्रष्टाचार के मंदिर पर बुलडोजर नहीं चला, तो रामराज्य की कल्पना सिर्फ नारों तक सीमित रह जाएगी।

सड़क पर फेंकी गई बुजुर्ग महिला की मेडिकल कालेज में मौत

» राम की नगरी में मां की ये दुर्गति... ये कैसी अयोध्या?

» बुजुर्ग महिला को लावारिस की तरह फेंकने वालों की पुलिस कर रही है तलाश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। कोतवाली अयोध्या के गांव किशुनदासपुर के पास परिजनों द्वारा एक मां को सड़क पर छोड़कर फरार हो जाने का मामला गरम हो गया है। बेसहारा मां ने बीती रात मेडिकल कालेज में अंतिम सांसें लीं। कोई ज़माना था जब वह भी घर की लक्ष्मी थी। अब वही घरवाले उसे गुपचुप सड़क किनारे छोड़ भाग निकले जैसे कोई पुराना सामान, कोई बेकार वस्तु।

बुधवार की रात, किशुनदासपुर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे ने मानवता का सबसे स्याह चेहरा रिकॉर्ड किया दो महिलाएं, एक बुजुर्ग मां, और एक खामोश विदाई। वो कोई विदा नहीं थी... वो समाज के मुंह पर तमाचा थी।पुलिस जब सुबह पहुंची, तब तक मां दर्द की परतों में लिपटी हुई बेसुध पड़ी थी। गले पर घाव था, सांसें डगमगाती थीं।

दर्शननगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में जिंदगी ने हार मान ली। कोतवाली अयोध्या के दर्शन नगर चौकी इंचार्ज जगन्नाथ मणि त्रिपाठी ने खुद बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी धड़कनों को समाज की बेरुखी ने पहले ही बंद कर दिया था।

स्वराज इंडिया का विशेष आग्रह

यदि आपने भी उस रात किशुनदासपुर के पास कोई ई-रिक्शा, या दो महिलाओं को बुजुर्ग के साथ देखा हो, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। क्योंकि इस समाज को केवल पुलिस नहीं, बल्कि जागरूक लोग ही बदल सकते हैं।

तलाश गश्ती

नाम/पता :- अज्ञात

हुलिया
1. आयु लगभग 80 वर्ष
2. रंग सांवला
3. आँख, कान, नाक औसत।

पहनावा
लाल व हरी मैक्सी, गले में सफ़ेद पट्टी

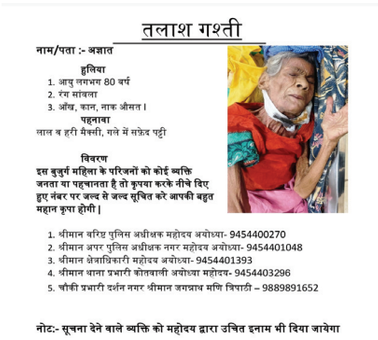

विवरण
इस बुजुर्ग महिला के परिजनों को कोई व्यक्ति जनता या पहचानता है तो कृपया करके नीचे दिए हुए नंबर पर जल्द से जल्द सूचित करे आपकी बहुत महान कृपा होगी।

1. श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय अयोध्या- 9454400270
2. श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय अयोध्या- 9454401048
3. श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय अयोध्या- 9454401393
4. श्रीमान थाना प्रभारी कोतवाली अयोध्या महोदय- 9454403296
5. चौकी प्रभारी दर्शन नगर श्रीमान जगन्नाथ मणि त्रिपाठी – 9889891652

नोट:- सूचना देने वाले व्यक्ति को महोदय द्वारा उचित इनाम भी दिया जायेगा

जन्म देने वाली मां को क्यों फेंक दिया गया?

पुलिस को आशंका है कि महिला किसी गंभीर संक्रामक बीमारी से पीड़ित थी, और परिवार इलाज कराने में असमर्थ था या शायद, अनिच्छुक। कंगाली और कलंक के बीच जूझता समाज अब बूढ़े मां-बाप को बोझ समझने लगा है।

सीसीटीवी में कैद हुआ अपराध

वो दो महिलाएं कौन थीं?

वो ई-रिक्शा कहां से आया?

और क्या सचमुच कोई विकल्प नहीं था सिवाय मां को मरने के लिए छोड़ने के? इन सवालों के जवाब खोजने में पुलिस जुटी है, लेकिन जवाब से ज्यादा डर अब उस सोच का है जो अपनों को अजनबी बना देती है।मंदिरों की घंटियों के बीच, एक मां की चीखें कहीं दब गईं। संस्कारों की भूमि पर एक बेसहारा शरीर इस इंतज़ार में पड़ा रहा कि कोई अपनाएगा लेकिन जो खून के रिश्ते थे, वो संक्रमण से ज्यादा खतरनाक निकले।

रिलीव ऑर्डर जारी, पर कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं बाबू जी!

» अयोध्या बिजली विभाग में बाबू की कुर्सी प्रेम गाथा चर्चा का विषय

» डेढ़ दशकों से अयोध्या में जमे लिपिक का तबादला बन गया विभागीय रहस्य

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। बिजली विभाग अयोध्या में इन दिनों तबादलों की आंधी चली है। कर्मचारी इधर से उधर कर दिए गए, अधिकांश ने समय से कार्यमुक्त होकर नई तैनाती ग्रहण कर ली। मगर एक नाम है जो सबके तबादले के बाद भी बिजली विभाग की कुर्सी से यूं चिपका है जैसे फेविकोल से जोड़ा गया हो लिपिक संजय वर्मा!

बता दे कि करीब डेढ़ दशक से अयोध्या में जमे लिपिक संजय वर्मा का स्थानांतरण तो हो गया, लेकिन वह रिलीव नहीं हुए। आदेश की स्याही सूख गई, या किसी जेब में सुखा दी गई यह चर्चा अब दफ्तर की गलियों से निकलकर विभागीय गरिमा पर सवाल बन चुकी है। ग़ौरतलब है कि जहां अन्य कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया गया,

वहीं संजय वर्मा पर जैसे 'रिलीव प्रतिबंध' लगा हो। सवाल उठने लाजिमी हैं। क्या आदेश कागज़ों तक सीमित था?

क्या फाइल जानबूझकर रोक दी गई? या फिर संजय वर्मा का विभाग से रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा है?

रिलीव-प्रूफ कर्मचारी बनते संजय वर्मा?

स्थानीय कर्मचारियों के बीच संजय वर्मा अब 'रिलीव-प्रूफ' क्लर्क के नाम से चर्चित हो रहे हैं। कुछ इसे 'संबंधों की ताकत' बता रहे हैं तो कुछ इसे 'प्रशासन की नाकामी' का नमूना।

वरिष्ठ अधिकारी मौन, कौन दे रहा सरंक्षण?

विभाग के अधीक्षण अभियंता भले ही संजय वर्मा की कार्यशैली की तारीफ करें, पर तबादले के बावजूद विदाई न होना कई बातों की ओर इशारा करता है।

क्या वाकई यह 'विशेष स्नेह' है या 'व्यवस्था की विशेष सेटिंग'? जब इस संबंध में अधीक्षण अभियंता से बात करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नही उठा।

अब सवाल उठता है...

क्या विभागीय नियम सब पर समान रूप से लागू नहीं होते?

क्या शासनादेश भी पसंद-नापसंद के आधार पर चलते हैं?

और सबसे बड़ा—यह रिश्ता क्या कहलाता है?

जनचर्चा है कि अगर तबादले के बाद भी कोई कर्मचारी कुर्सी से न हटे, तो समझ लीजिए वो कुर्सी नहीं, कोई सिस्टम है!

छह घंटे तक धरने पर बैठीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला

कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे का विरोध, जांच के आश्वासन पर मानीं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के बदलापुर गांव में आरसीसी सड़क निर्माण को लेकर उपजा विवाद गुरुवार को धरने तक पहुंच गया। कार्यकर्ताओं पर हुए एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे के विरोध में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला गुरुवार दोपहर पौने तीन बजे अकबरपुर थाने में धरने पर बैठ गईं और कोतवाल व चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की रख दी। अधिकारियों के जांच के आश्वासन पर उन्होंने धरना खत्म किया और मांग पूरी न होने पर फिर से धरने की चेतावनी दी।

यह है पूरा मामला : अकबरपुर क्षेत्र के बदलापुर गांव में करीब 25 वर्षों से बदहाल सड़क का निर्माण विधायक निधि से कराया जा रहा है। दो दिन पूर्व वहां के सभासद शमसाद ने काम रुकवा दिया था, जिसके बाद उत्पन्न हुए विवाद में सभासद पर सरकारी कार्य में बाधा डालने व रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, गुरुवार को सभासद के समर्थक गांव के ही बाबूराम गौतम ने मंत्री समर्थक अबरार, मो. यूसुफ, असलम, यासिर व शिवा पांडेय पर एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया कि आपस में चर्चा होने पर उसने सही बात रखी तो उसे जातिसूचक शब्द कहे। कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे के विरोध में गुरुवार दोपहर करीब 2:45 पर राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला कार्यकर्ताओं संग अकबरपुर थाने पहुंच गईं और कोतवाल सतीश सिंह व लालपुर चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग को लेकर थाने के मुख्यद्वार पर करीब 70-80 कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गईं। सीओ प्रिया सिंह ने उनसे वार्ता कर कार्यालय में बैठने की गुजारिश, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वहीं अपराह्न साढ़े तीन बजे के करीब एएसपी राजेश पांडेय पहुंचे, जिसके आधे घंटे बाद एसपी अरविंद मिश्रा अकबरपुर थाने पहुंचे। उन्होंने कार्यालय में बैठकर वार्ता करने की बात कही, जिस पर राज्यमंत्री ने मना कर दिया डीएम आलोक कुमार सिंह भी आए, लेकिन बात नहीं बन सकी। वहीं, रात आठ बजे तक मामला नहीं सुलझ सका। वहीं साढ़े सात बजे के करीब पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी भी कार्यकर्ताओं के साथ अकबरपुर थाने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज

इस घटना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने घटना का वीडियो शेयर करते लिखा कि सत्ताधारी राज्यमंत्री महोदया खुद ही अपनी पुलिस की करतूतों के खिलाफ धरना दे रही हैं, मुख्यमंत्री जी को कुछ और सबूत चाहिए क्या? भाजपा जाएगी तो पुलिस व्यवस्था आएगी।

थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू

डीएम आलोक सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा द्वारा स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी को हटाने और थाना प्रभारी सतीश सिंह के खिलाफ जांच के आदेश देने के बाद धरना समाप्त किया गया। उन्होंने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडेय को मामले की विस्तृत जांच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिये गये हैं।

शिव मंदिर
जिसके लिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ा युद्ध

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। हजार साल पुराने शिव मंदिर को लेकर दो एशियाई देश आपस में भिड़ गए हैं। यह मंदिर भारत में नहीं हैं। आपसी में लड़ने वाले यह दो देश थाईलैंड और कंबोडिया हैं। बीते दिन थाईलैंड ने एफ16 लड़ाकू विमान से कंम्बोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इस युद्ध में अभी तक 40 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह शिव मंदिर थाइलैंड और कंबोडिया की सीमा पर मौजूद है। इसके लिए दोनों देश लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें दो बार कंबोडिया की जीत भी हो चुकी है, लेकिन यह विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मंदिर धार्मिक नहीं बल्कि दो देशों के बीच राष्ट्रवाद का मुद्दा बन गया है।

प्रीह विहियर शिव मंदिर : भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का नाम प्रीह विहियर मंदिर है। यह कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज (NESCO) में शामिल किया है।

सरकार पर 'वार'
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सम्मेलन में कई मुद्दों का जिक्र किया

पीएम पर तीखा वार, बीजेपी-आरएसएस पर भी साधा निशाना

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'झूठों के सरदार' हैं। झूठ बोलना ही उनका काम है। उन्होंने देश से झूठ बोला कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, विदेश से कालाधन लाऊंगा। सबको 15-15 लाख दूंगा। किसानों को एमएसप दूंगा। बैकवर्ड क्लास की आमदनी बढ़ा दूंगा। नरेंद्र मोदी संसद तक में झूठ बोलते हैं। इसलिए हमें लोगों को समझाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री देश, समाज का भला नहीं कर सकते।

» जातिगत जनगणना कराना व आरक्षण में 50% की सीमा को खत्म करना हमारी मांग

» पीएम उन्हें आरक्षण नहीं देना चाहते, जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, हम उनके साथ खड़े

"भागीदारी न्याय सम्मेलन" में जमकर गरजे खरगे : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी की ओर से आयोजित 'भागीदारी न्याय सम्मेलन' में कई मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि यहां बहुत भारी संख्या में लोग जुटे हैं और वे अपने हक के बारे में समझते हैं। देश में जातिगत जनगणना कराना और आरक्षण में 50 फीसदी की सीमा को खत्म करना हमारी मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आरक्षण नहीं देना चाहते, जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं।